बी.ए. (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत और विश्व इतिहास

अध्याय: शीत युद्धोत्तर घटनाक्रम

लेखक: डॉ. रजनीश कुमार गुप्ता

विभाग: राजनीति विज्ञान विभाग

कॉलेज: मोतीलाल नेहरू कॉलेज

अध्याय:शीत युद्धोत्तर घटनाक्रम

1.0 परिचय

1.1सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

1.1.1 उदारवादी

1.1.2 यथार्थवादी

1.1.3 चरमपंथी

1.2 प्रतिद्वंदी रूझान

1.2.1 वैश्वीकरण और विखंडन

1.2.2 एकधुव्रीयता और बहुधुव्रीयता

1.2.3 आर्थिक एकीकरण और सैन्य गठबंधन

1.2.4 अमेरिकी वर्चस्व और तृतीय विश्व

1.2.5 ग्लोबल कॉमन्स, अंतर-राज्यीय प्रतिद्वंद्विता और वैश्विक खतरे

1.3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम

1.3.1 खाड़ी युद्ध

1.3.2 अफगानिस्तान में तालिबानी शासन

1.3.3 अमेरिका में आतंकवादी हमला

1.3.4 आतंकवाद के खिलाफ युद्ध

1.3.5 विश्व व्यापार संगठन' की स्थापना

1.3.6 पर्यावरणीय मुद्दे

1.3.7 संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका

- सारांश
- अभ्यास के लिये प्रश्न
- पारिभाषिक शब्द
- समझ की परख: उत्तर
- सन्दर्भ

1.0 परिचय

"दुनिया एक युग को छोड़ कर दूसरे युग में प्रवेश कर रही है। हम एक दीर्घकालिक स्थायी और शांतिपूर्ण युग की शुरुआत कर रहे हैं। शक्ति के भय की धमकी, अविश्वास, मनोवैज्ञानिक और वैचारिक संघर्ष ये सब अब अतीत की बातें होना चाहिए।...मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को आश्वासन दिया कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ कभी भी एक गर्म युद्ध की शुरूआत नहीं करूंगा।"

-मिखाइल गोर्बाचेव (दिसम्बर 1989 ई. में आयोजित माल्टा बैठक के पश्चात संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में)

"हम एक दीर्घकालिक शांति का एहसास कर सकते हैं और पूर्व-पश्चिम रिश्ते को सतत सहयोग में बदल सकते हैं। यही वह भविष्य है जिसकी मैंने और गोर्बाचेव ने माल्टा में शुरूआत की है।"

-जॉर्ज डब्लू. बुश (दिसम्बर 1989 ई. में आयोजित माल्टा बैठक के पश्चात संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में)

चित्र-1

मिखाइल गोर्बाचेव और जॉर्ज डब्लू. बुश माल्टा बैठक के दौरान

स्रोत: http://en.wikipedia.org/wiki/Malta_Summit#mediaviewer/File:Bush_and_Gorbachev_at_the_Malta_summit_in_1989.gifaccessed on 12 November 2014।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसका गत्यात्मक स्वरुप । समय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना और प्रकृति में व्यापक बदलाव आते रहे हैं जो कि मुख्यतः भू-

राजनीतिक और भू-आर्थिक परिवेश से प्रभावित रहे हैं। उन्नीसवीं सदी की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मोटे तौर पर यूरोप के विकसित देशों द्वारा दुनिया के अन्य हिस्सों में अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के प्रसार पर केन्द्रित रही। बीसवीं सदी का पूर्वार्ध विश्व की प्रमुख शक्तियों के परस्पर विरोधी हितों के टकराव से उपजे दो विश्व युद्धों का साक्षी बना। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दशकों तक दो महाशक्तियों के मध्य बनी 'शीत युद्ध' की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रबिंदु बनी रही। पुनश्च, सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध के अंत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्रांतिकारी बदलाव लाये। जहाँ एक ओर सैद्धांतिक दृष्टि से विद्वानों ने 'नवीन विश्व व्यवस्था' के उदय की व्याख्याएँ दीं तो वहीं व्यवहारिक तौर पर इस युग में अनेक नवीन संभावनाओं और चुनौतियों ने दस्तक दी।

1.1 सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

शीत युद्ध के अंत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक बदलावों की शुरूआत की। बदली हुई परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना और प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों की विद्वानों ने विविध दृष्टिकोणों से व्याख्या की जिसके परिणामस्वरूप अनेक सैद्धांतिक दृष्टिकोण उभरे। इस सन्दर्भ में मोटे तौर पर तीन प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोणों को रखा जा सकता है- उदारवादी, यथार्थवादी और चरमपंथी।

1.1.1 उदारवादी

उदारवादी परिप्रेक्ष्य शीत युद्ध के अंत को अत्यंत आशावादी नजरिये से देखता है । इस आशावाद का आधार उदारवाद की तीन मूलभूत मान्यताएं हैं- लोकतंत्रों में आपसी संघर्ष नहीं होता, संस्थानिक ढाँचे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अराजक स्वरुप को समाप्त किया जा सकता है और समकालीन वैश्विक पूंजीवाद राज्यों के मध्य सघन संपर्क स्थापित करता है । शीत युधोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या में फ्रांसिस फुकुयामा की 'इतिहास के अंत' की अवधारणा उदारवादी परिप्रेक्ष्य की प्रतिनिधि विचारधारा मानी जाती है। फुकुयामा के अनुसार, फ्रांसीसी क्रांति के बाद से इतिहास में समष्टिवाद का समर्थन करने वाली शक्तियों और 'बुर्जुआ' व्यक्तिवाद के आदर्शों में विश्वास करने वालों के मध्य एक गतिशील संघर्ष रहा है। सन् 1917 ई. की रूसी क्रांति के पश्चात से इस संघर्ष में समष्टिवाद का पलड़ा भारी रहा किन्तु 1970 के दशक तक इसमें बदलाव दृष्टिगोचर होने लगे और तीसरी दुनिया के अनेक देशों में आर्थिक नियोजन की विफलताएं नजर आने लगीं, सन् 1985 ई. में सोवियत संघ में गोर्बाचेव के सत्तारूढ़ होने के पश्चात से ये बदलाव और भी स्पष्ट हो गये। उन्होंने न केवल सोवियत संघ की परंपरागत मान्यताओं को चुनौती दी बल्कि अपने सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से 'बाज़ार अर्थव्यवस्था' का मार्ग भी प्रसस्त किया। इस प्रकार अंततः समष्टिवाद पर व्यक्तिवाद की विजय हुई (एम. कॉक्स)। फुकुयामा ने पूंजीवाद की इस विजय को इतिहास के अंत के रूप में परिभाषित किया। यहाँ इतिहास के अंत का अर्थ यह नहीं है कि ऐतिहासिक घटनाओं का सिलसिला थम गया है, वह तो अनवरत है

किन्तु इस क्रम में लगातार चल रहे संघर्ष का अंत हो गया है । फुकुयामा का तर्क है कि अब 'बाज़ार अर्थव्यवस्था' और पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं है इसलिए एक तरह से इतिहास ठहर गया है।

क्या आप जानते हैं?-1

फ्रांसिस फुकुयामा कौन हैं?

स्रोत: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francis_Fukuyama_2005.jpg accessed on 9 December 2014

फ्रांसिस फुकुयामा अमेरिका के राजनीतिशास्त्री हैं। आपका जन्म 27 अक्टूबर 1952 को हुआ । वह वर्तमान में स्तानफोर्ड विश्वविद्यालय में सीनियर फेलो हैं । उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'इन्ड ऑफ़ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन' वर्ष 1992 में प्रकाशित हुई।

1.1.2 यथार्थवादी

यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य शीत युधोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अत्यंत धूमिल तस्वीर का चित्रण करता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण के तर्क अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास के सम्बन्ध में उनके तीन आकलनों पर आधारित हैं- यह सदैव ही प्रतिस्पर्धी और अराजक रही है, नवीन विश्व व्यवस्था के निर्माण के सारे प्रयास प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात से ही नाकामयाब रहे हैं और 1989 के पश्चात से विश्व में 'विफल राज्यों', 'बर्बर युद्धों' और विघटित क्षेत्रों की बाढ़ सी आ गयी है । जॉन मेअर्शेइमेर ने अपने शोधपत्र 'बैक टू द फ्यूचर' में तर्क दिया कि शीत युद्ध की द्विध्रुवीय राजनीति ने विश्व में स्थिरता और व्यवस्था की स्थापना की थी और सोवियत संघ के विघटन तथा शीत युद्ध की समाप्ति अनेक नवीन चुनौतियों को जन्म दे सकती है, जिनमें प्रमुख हैं- परमाणु प्रसार , जातीय संघर्ष और विखण्डनीकरण की समस्याएँ। रॉबर्ट डी कापलान ने अपनी प्रसिद्ध 'कमिंग अनार्की' की संकल्पना के माध्यम से शीत युधोत्तर युग में पतन और विघटन की घटनाओं में हो रही अभूतपूर्व वृद्धि पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपनी यह अवधारणा अफ्रीका जैसे महाद्वीपों के अनुभवों पर विकसित की तथा इन्हें 'मरणशील क्षेत्र' की संज्ञा प्रदान की। कापलान के अनुसार पश्चिम इन क्षेत्रों की उपेक्षा अपने जोखिम पर कर रहा है। तथापि इस सन्दर्भ में सबसे चर्चित बहस की शुरूआत का श्रेय सैमुएल पी. हंटिंगटन को जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि शीत युद्ध के पतन से भले ही मुक्त आर्थिक विचारधाराओं की विजय हो गयी हो किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि विश्व से संघर्षों की समाप्ति हो गयी है । हटिंगटन के अनुसार शीत युधोत्तर युग में संघर्ष अपने नवीन स्वरुप में अभिव्यक्त होगा जिसे उन्होंने 'सभ्यताओं के संघर्ष' के रूप में चित्रित किया। 'सभ्यताओं के संघर्ष' संबंधी हटिंगटन के विचार संघर्ष की अनिवार्यता के एक ऐतिहासिक सिद्ध तथ्य की प्राथमिक मान्यता पर आधारित हैं और इस निष्कर्ष पर पर पहुँचते हैं कि अब दुनिया में संघर्ष मुख्यतः सांस्कृतिक होगा।

मानचित्र-1

सैमुएल पी. हंटिंगटन द्वारा कल्पित सभ्यताओं के संघर्ष के क्षेत्र

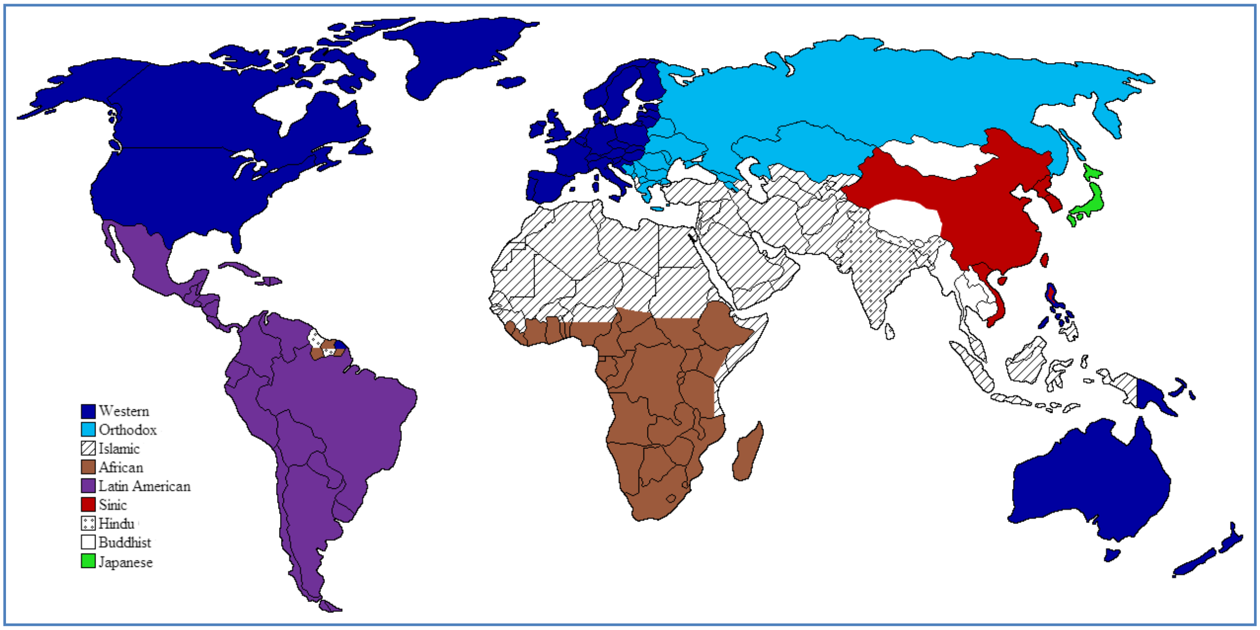

स्रोत: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clash_of_Civilizations_map.png accessed on 19 December 2014

1.1.3 चरमपंथी

उदारवादी और यथार्थवादी विद्वानों के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ अध्येता शीत युधोत्तर युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, नोम चोमस्की मौजूदा विश्व व्यवस्था के उस यथार्थ स्वरुप का चित्रण करते हैं जिसमें शक्तिशाली लोग दुर्बलों का शोषण करते हैं, अमीर जनसाधारण के साथ हेरफेर करते हैं और महाशक्तियां कमजोर देशों पर हावी हैं। चोम्स्की के अनुसार, मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अमेरिकी प्रभुत्व की संरचना करती है और निश्चित रूप से सौहार्दपूर्ण नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया में एक आक्रामक और निर्मम प्रधानत्व स्थापित कर रखा है जिसका मुख्य उद्देश्य है अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये विश्व भर में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना । चोम्स्की का तर्क है कि लोकतंत्र, मानव अधिकारों और सम्बंधित क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वघोषित नैतिक नीतियां वस्तुतः उसके अपने हितों से प्रेरित हैं। एक अन्य विद्वान रॉबर्ट कॉक्स का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आधारभूत परिवर्तनों की शुरूआत 1980 के दशक के अंत या 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में नहीं हुई। वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण 'राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण' से करते हैं और तर्क देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ढांचे में बड़ा बदलाव 1970 के दशक के मध्य में आए आर्थिक संकट के पश्चात दृष्टिगोचर हुआ। उनके अनुसार 1970 के दशक में कीनेसियन औद्योगिक विकास की नीतियों का अनुपालन करने वाले कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर केन्द्रित देशों की नीतियों में व्यापक बदलाव

आये और वे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था पर जोर देने लगे। इस बदलाव से समृद्ध देशों में व्यापक आर्थिक वृद्धि आयी और उन्होंने अपार सम्पदा इकट्ठी की किन्तु अधिकाँश देशों में यह व्यापक गरीबी और विपत्ति का कारक बना और 1989 के पश्चात से इसमें और वृद्धि हुई । शीत युद्ध कालीन अस्पष्ट विचारधारात्मक रूझान और राजकीय ढांचा इन देशों में कमोबेश आज भी वैसा ही बना हुआ है । इन परिस्थितियों में जहाँ एक ओर पारंपरिक मार्क्सवादी अर्थों में वर्ग क्रांति की संभावना न के बराबर है वहीं दूसरी ओर वैश्वीकरण से उपजी नवीन चुनौतियों की संभावना राजनीतिक एजेंडे पर बनी हुई है।

क्या आप जानते हैं?-2

नोम चोम्स्की कौन हैं?

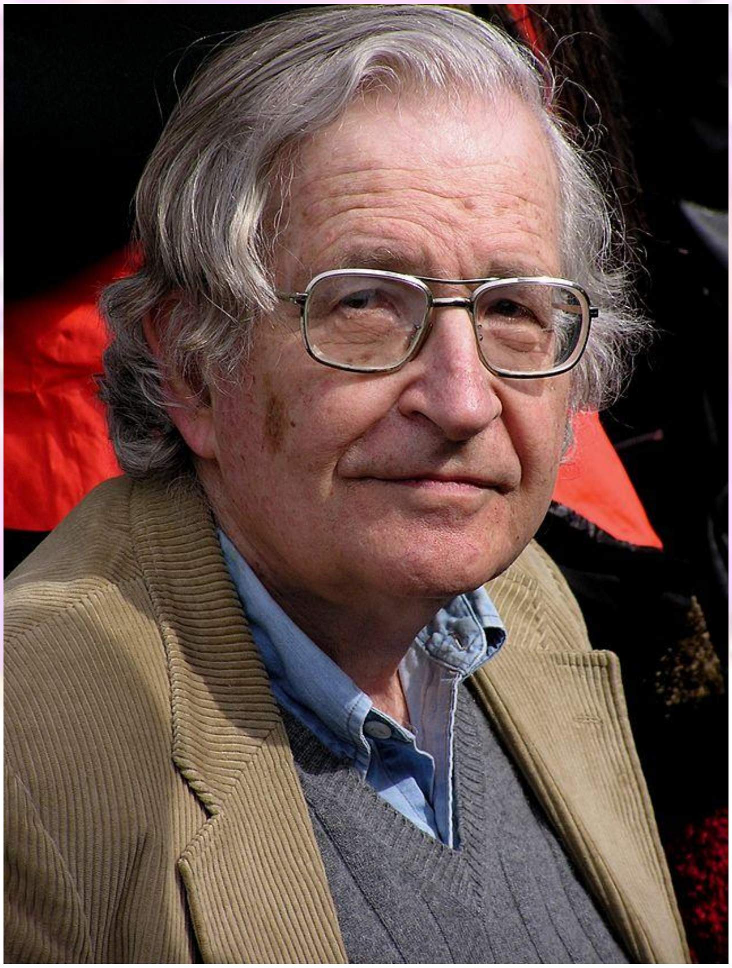

स्रोत: http://en.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky#mediaviewer/File:Chomsky.jpg accessed on 16 January 2015

नोम चोम्स्की का जन्म 7 दिसंबर 1928 को अमरीका में हुआ था। अपने राज नीतिक विचारों एवं अमेरिका की विदेश नीति की प्रखर आलोचना के लिए आज उन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उन्हें सर्वप्रथम ख्याति 1967 में प्रकाशित उनकी पुस्तक 'द रिसपांसिबिलिटी आफ इंटेलेक्चुअल्स' से मिली जिसमें वियतनाम युद्ध की कटु आलोचना की गयी थी । उनकी उल्लेखनीय पुस्तकों में शामिल हैं-अमेरिकन पावर ऐंड द न्यू मैंडरिन्स, एट वार विद एशिया, पीस इन द मिड्ल-ईस्ट? रिफ्लेक्शंस आन जस्टीस ऐंड नेशनहुड , ह्यूमन राईट्स ऐंड द अमेरिकन फारेन पालिसी , द पालिटिकल इकानमी आफ ह्यूमन राईट्स , आन पावर ऐंड आइडियोलजी , द कल्चर आफ टेरेरिज्म , व्हाट अंकल सैम रियली वांट्स, पावर ऐंड टेरर-पोस्ट :9/11 टाक्स ऐंड इंटर्व्यूज, हेजेमोनी और सरवाईवल अमेरिकाज क्वेस्ट फार : ग्लोबल डामिनेंस, इम्पीरियल एंबीशन्स कानवर्सेशन्स आन द पोस्ट :9/11 वर्ल्ड, व्हाट वी से गोज : कानवर्सेशन्स आन यूएस पावर इन ए चेंजिंग वर्ल्ड।

समझ की परख

(सही या गलत का चयन करें)

1 यथार्थवादियों के अनुसार लोकतंत्रों में आपसी संघर्ष नहीं होता।

2. नोम चोम्स्की अमेरिका की विदेश नीति की प्रखर आलोचना के लिए जाने जाते हैं।

3 'सभ्यताओं के संघर्ष' की अवधारणा रॉबर्ट कॉक्स ने दी।

4. शीत युधोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या में फ्रांसिस फुकुयामा की 'इतिहास के अंत' की अवधारणा उदारवादी परिप्रेक्ष्य की प्रतिनिधि विचारधारा मानी जाती है।

5 सैमुएल पी. हंटिंगटन के अनुसार शीत युद्ध के पतन से भले ही मुक्त आर्थिक विचारधाराओं की विजय हो गयी हो किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि विश्व से संघर्षों की समाप्ति हो गयी है।

1.2 प्रतिद्वंदी रूझान

द्वीतीय विश्व युद्ध के पश्चात लगभग चार दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना और प्रक्रिया शीत युद्ध के विविध आयामों द्वारा परिभाषित होती रही। स्पष्ट है कि शीत युद्ध के पतन के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत और व्यवहार में दूरगामी परिणाम हुए । आपने पिछले अनुभाग में इस सन्दर्भ में सैद्धांतिक विश्लेषणों को पढ़ा। इस भाग में शीत युधोत्तर युग में उभरे कुछ प्रतिद्वंदी रूझानों की चर्चा की जायेगी।

1.2.1 वैश्वीकरण और विखंडन

शीत युद्ध के बाद की अवधि में उभरी नई अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं- वैश्वीकरण का बढ़ता दायरा और राष्ट्र-राज्यों में बढ़ती विखंडन की प्रक्रिया। एक ओर परिवहन और संचार की तकनीकों में अभूतपूर्व प्रगति से दुनिया की भौगोलिक दूरियां तेजी से सिमट रही हैं और संसार एक 'वैश्विक गाँव' में परिवर्तित होता हुआ प्रतीत हो रहा है । दूसरी ओर, अनेक राज्यों में सामाजिक-जातीय संघर्षों में व्यापक वृद्धि हुई है और वे या तो अनेक भागों में बंट चुके हैं या फिर विघटन की कगार पर हैं। सोवियत संघ, यूगोस्लाविया एवम चेकोस्लाविया जैसे देश काल के गर्त में समा चुके हैं और इनका स्थान नवीन संप्रभु राज्यों ने ले लिया है। सूडान दो टुकड़ों में विभाजित हो गया और अफ्रीका महाद्वीप के अनेक देशों में जारी संघर्षमय परिस्थितियां अनेक देशों में विखंडन की आशंका पैदा कर रही हैं।

मानचित्र-2

यूगोस्लाविया के विघटन से नवोदित राज्य

स्रोत : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SocialistYugoslavia_en.svg accessed on 12 December 2014

महत्वपूर्ण तथ्य-1

दक्षिण सूडान

स्रोत: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SouthSudanStateshi.svg accessed on 11 January 2015

दक्षिण सूडान उत्तर-पूर्व अफ़्रीका में स्थित स्थल-रुद्ध देश है। यह देश 9 जुलाई 2011 को अफ्रीका के सबसे बड़े देश सूडान के विभाजन के फलस्वरूप अस्तित्व में आया । यह विश्व का 196वां स्वतंत्र देश , संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य तथा अफ्रीका का 55वां देश है। दक्षिण सूडान दस राज्यों में विभाजित है, जो तीन ऐतिहासिक क्षेत्रों के अंदर आते हैं: बहर अल ग़ज़ल , इक्वेटोरिया और ग्रेटर अपर नील। अपनी आजादी के समय से ही राष्ट्र को आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है।

1.2.2 एकध्रुवीयता और बहुध्रुवीयता

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संबंधों की संरचना को दर्शाने के लिये प्रायः ध्रुवीयता की शब्दावली का प्रयोग किया जाता रहा है। इसके अंतर्गत किसी समय की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में सत्ता के प्रमुख केन्द्रों का विश्लेषण किया जाता है । शीत युद्ध के दौरान प्रायः यह विश्वास किया जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना द्विध्रुवीय थी। किन्तु शीत युधोत्तर विश्व में ध्रुवीयता का प्रश्न विद्वानों के समक्ष गंभीर बहस का विषय रहा है। कुछ विद्वानों ने शीत युद्ध के पश्चात के युग का वर्णन एकध्रुवीय विश्व के रूप में किया जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका सर्वशक्तिमान है जबकि अन्य विद्वान 'बहुध्रुवीय दुनिया' की पैरोकारी करते हैं। वर्तमान विश्व में व्याप्त एकध्रुवीयता की वकालत करने वाले विद्वानों के अनुसार सोवियत संघ के पतन के पश्चात अपनी आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक शक्ति के बल पर संयुक्त राज्य अमेरिका समूचे संसार में अपने प्रभाव का विस्तार करने में सक्षम रहा है और इस प्रकार विश्व का

शक्ति संतुलन निर्विवाद रूप से उसके पक्ष में रहा है। वहीं दूसरी ओर, कई विद्वानों का तर्क है कि शीत युद्ध के अंत के बाद से पिछले दो दशकों में दुनिया में शक्ति-संतुलन की दृष्टि से अनेक मौलिक बदलाव आये हैं और अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने वाली अनेक प्रतिद्वंद्वी शक्तियों का आविर्भाव हुआ है इनमें से मुख्यतः यूरोपीय संघ, चीन, जापान, रूस, भारत और ब्राजील की गणना की जाती है।

क्या आप जानते हैं?-3

हाइपरपॉवर क्या है?

हाइपरपॉवर उस शक्ति को कहा जाता है जो कि मानवीय जीवन के हर एक पहलू पर अन्य राज्यों के ऊपर हावी होता है। हाइपरपॉवर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रचलित महाशक्ति की शब्दावली से अधिक शक्तिशाली होता है और अन्य किसी प्रतिद्वंद्वी शक्ति के अभाव में इसकी तुलना में अन्य राज्यों की स्थिति गौंड होती है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश पत्रकार पेरेग्रिन वोर्स्थोरने ने शीत युधोत्तर विश्व में संयुक्त राज्य अमरीका की स्थिति दर्शाने हेतु 3 मार्च 1991 को संडे टेलीग्राफ में प्रकाशित अपने आलेख 'बुश डॉक्ट्रिन' में किया।

1.2.3 आर्थिक एकीकरण और सैन्य गठबंधन

शीत युद्ध की अवधि में वैचारिक प्रतिद्वंद्विता पर आधारित 'सैन्य गठबंधनों' का प्रभुत्व रहा । जहाँ एक ओर पूंजीवादी धड़े के देश नाटो (नार्थ अटलांटिक ट्रीटी आर्गेनाइजेशन), सीटो (साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी आर्गेनाइजेशन) और सेन्टो (सेंट्रल ट्रीटी आर्गेनाइजेशन) जैसे सैन्य गठबन्धनों से बंधे हुए थे तो इनके जवाब में साम्यवादी गुट के अनेक देशों ने मिलकर 'वारसा संधि' की स्थापना कर रखी थी। शीत युधोत्तर युग में यद्यपि सैन्य गठबन्धनों के स्थान पर आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रचलन में आयी है और दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार के आर्थिक गठबंधन अस्तितत्व में आये हैं जैसे यूरोपीय संघ, आसियान, नाफ्टा, दक्षेस, लाफ्टा, मर्कोसुर इत्यादि। तथापि नाटो जैसा सैन्य गठबंधन न केवल आज भी विद्यमान है बल्कि शीत युद्ध के अंत के बावजूद इसकी सदस्यता में विस्तार भी हुआ है।

महत्वपूर्ण तथ्य-2

नाटो का विस्तार

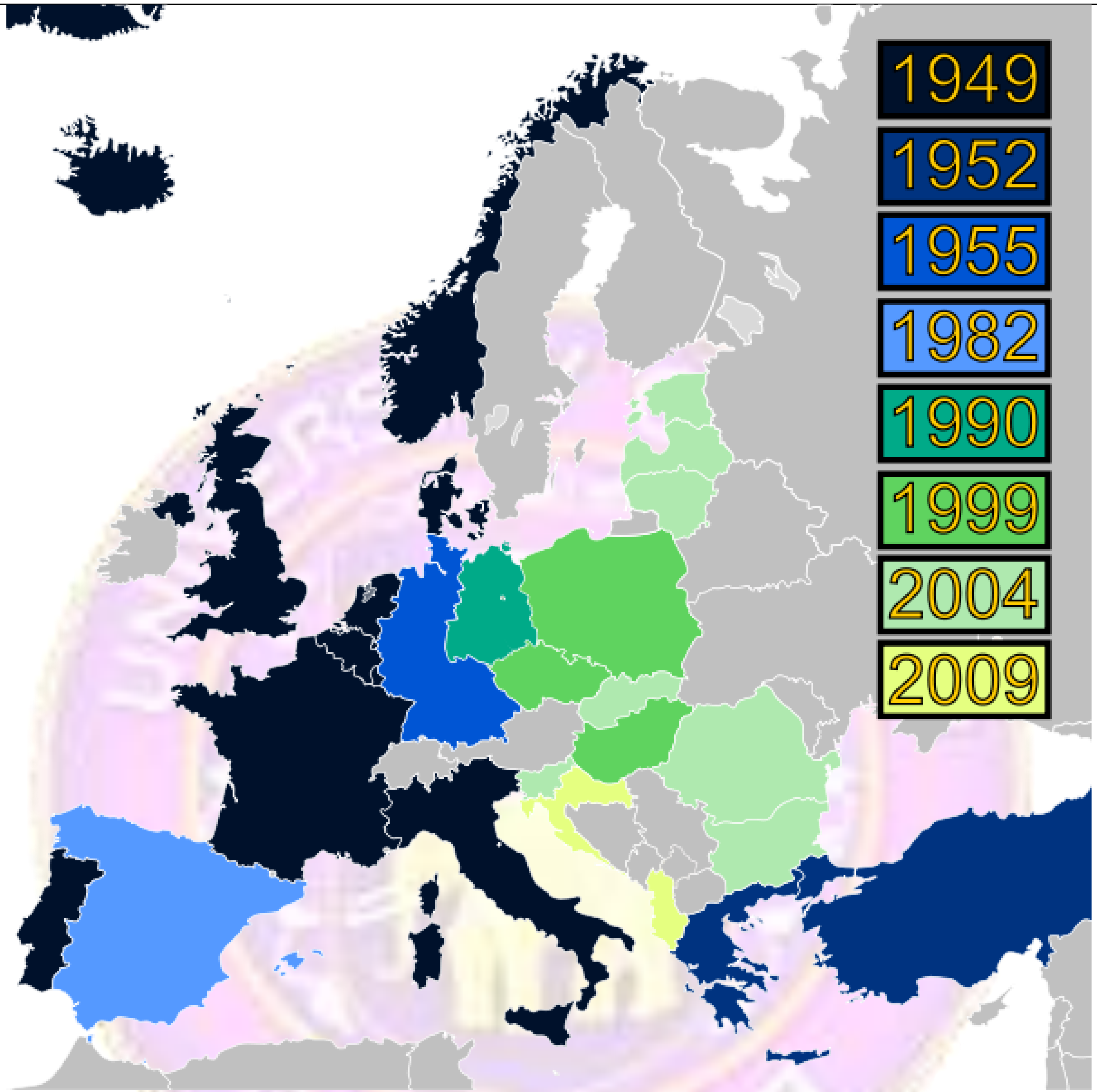

स्रोत: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:History_of_NATO_enlargement.svg accessed on 8 February 2015

नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। स्थापना के समय इसमें 12 सदस्य देश शामिल थे- बेल्जियम , कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। 1952 में नाटो का पहला विस्तार हुआ और इसमें यूनान और तुर्की को शामिल किया गया। 1955 में इसमें पश्चिमी जर्मनी और 1982 में इसमें स्पेन शामिल हुये। शीत युद्ध के पश्चात इसकी सदस्यता का पूर्वी यूरोप के देशों तक विस्तार करते हुए 1999 में इसमें पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य को शामिल किया गया । वर्ष 2004 में एक बार पुनः नाटो का विस्तार हुआ और इसमें एस्टोनिया , लातविया, लिथुआनिया , स्लोवेनिया, स्लोवाकिया , बुल्गारिया और रोमानिया को शामिल

किया गया। नाटो का अंतिम विस्तार 2009 में हुआ और इसमें अल्बानिया तथा क्रोएशिया को सदस्यता प्रदान की गयी। वर्तमान में बोस्निया-हर्जेगोविना , जॉर्जिया, मैसिडोनिया और मोंटेनेग्रो भी नाटो की सदस्यता प्राप्त करने की कगार पर हैं।

1.2.4 अमेरिकी वर्चस्व और तृतीय विश्व

शीत युधोत्तर युग में विकसित और विकासशील देशों के हितों में स्पष्टतः विरोधाभास दृष्टिगोचर हुए हैं। हितों के ये टकराव अंतर्राष्ट्रीय मंचों- संयुक्त राष्ट्र संघ, इंटरनेशनल मोनेटरी फण्ड (आईएमएफ), विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन इत्यादि अथवा अन्य संगठनों जैसे जी-8, जी-77, गुटनिरपेक्षता आन्दोलन की गतिविधियों में देखे जा सकते हैं । जहाँ एक ओर संयुक्त राज्य अमेरिका ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग अपना वर्चस्व बनाये रखने हेतु किया है वहीं भारत और चीन जैसे देशों ने इन संस्थाओं में आधारभूत सुधार करने और इन संस्थाओं में तृतीय विश्व के विकासशील देशों के हितों को संरक्षित करने की दृष्टि से अपनी आवाज बुलंद की है । अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद साठ के दशक में जन्मा गुटनिरपेक्षता आन्दोलन आज भी अस्तित्व में है और यदाकदा ही सही दक्षिण-दक्षिण सहयोग की आवाज गुंजायमान होती रहती है।

चित्र-2

अमेरिकी वर्चस्व को दर्शाता एक कार्टून

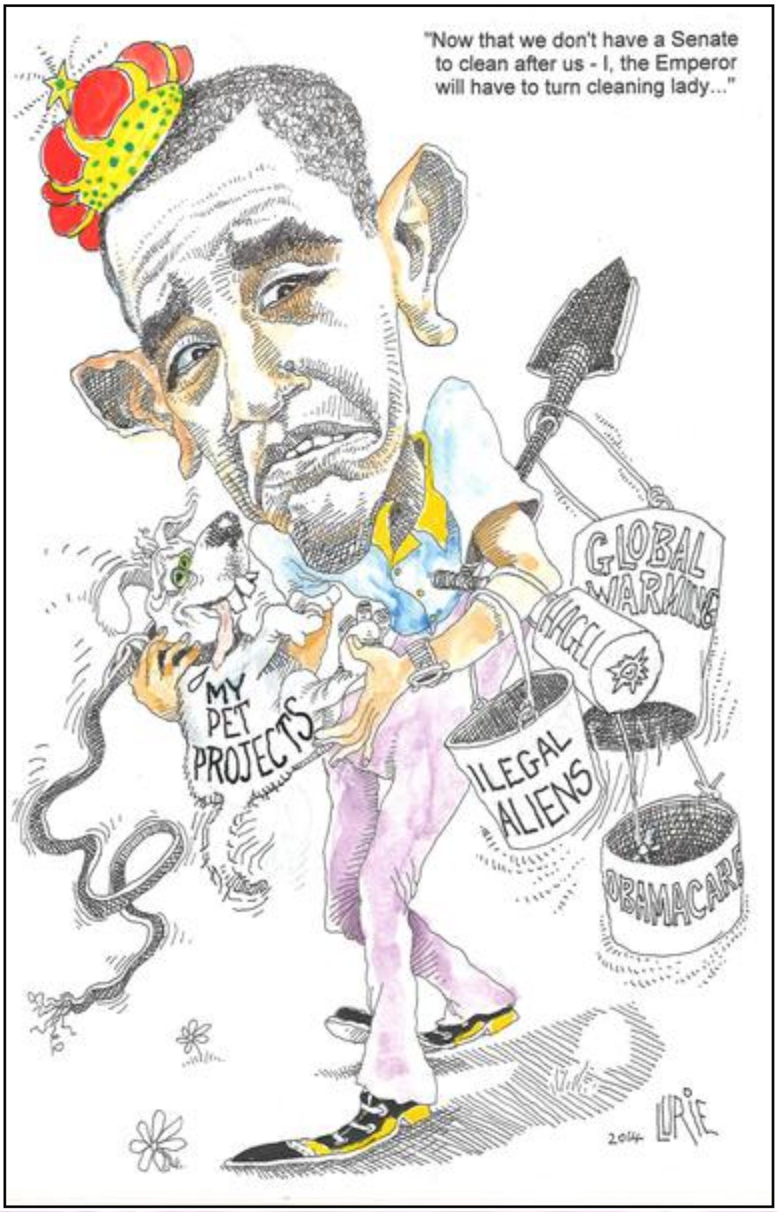

स्रोत: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emperor_Obama,_by_Ranan_Lurie.png accessed on 18 February 2015

1.2.5 ग्लोबल कॉमन्स, अंतर-राज्यीय प्रतिद्वंद्विता और वैश्विक खतरे

मानचित्र-3

ग्लोबल वार्मिंग की भयावह तस्वीर

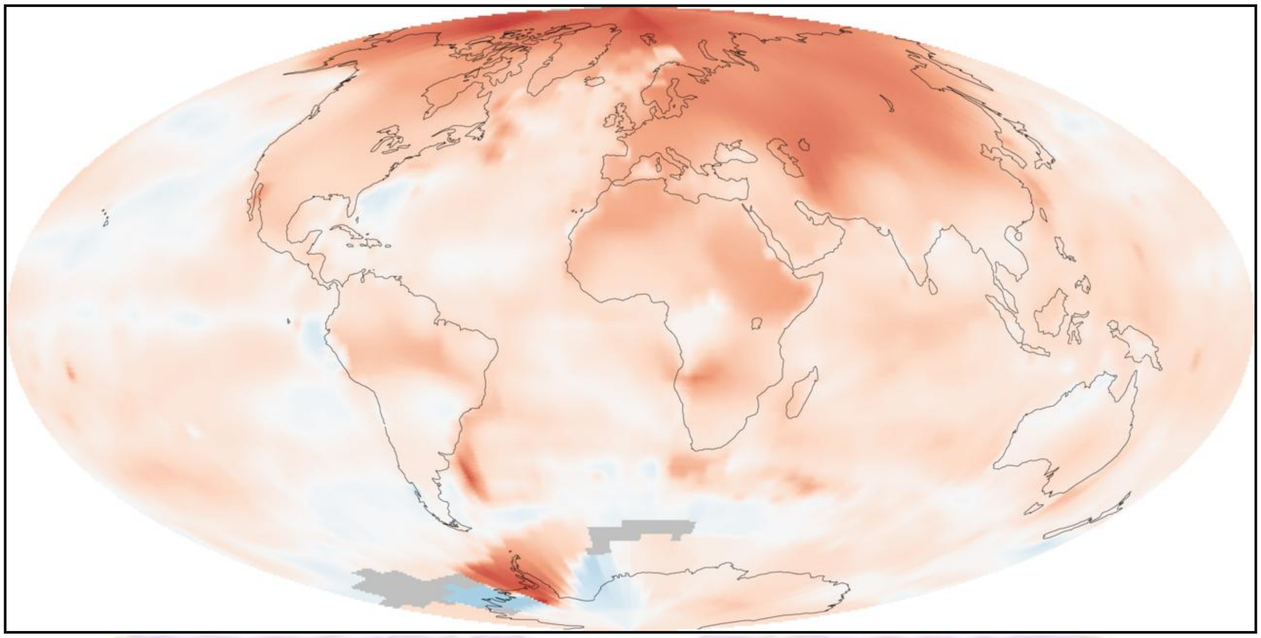

स्रोत:http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming#mediaviewer/File:GISS_temperature_2000-09_lrg.png accessed on 18 February 2015

शीत युद्ध के पश्चात की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अनेक मायनों में वास्तविक तौर पर वैश्विक बन गयी है। एक तरफ संचार और यातायात के साधनों के द्रुतगामी विकास ने आवागमन को सरल बना दिया है और वैश्विक स्तर पर मानव प्रवास की दर बढी है, तो दूसरी ओर अनेक ऐसी चुनौतियों ने जन्म लिया है जिनका सामना राष्ट्र-राज्यों की परिधि के भीतर रहकर नहीं किया जा सकता । वहीं यदि इनसे भली प्रकार न निपटा गया तो ये समस्याएँ हमारे अस्तित्व को ही ख़त्म कर सकती हैं । इस प्रकार 'ग्लोबल कॉमन्स' की अवधारणा का तेजी से प्रसार हुआ है जिसके अंतर्गत इस तथ्य को मान्यता दी जाती है कि दुनिया की सम्पदा के कुछ हिस्से जैसे कि हमारा जैव मंडल हमारी साझा संपत्ति है और इनको बचाने की हम सब की बराबर की जिम्मेदारी है । किन्तु इसके साथ ही साथ हम दुनिया के तमाम हिस्सों में अंतः राज्यीय संघर्ष और विविध देशों के बीच संघर्ष में भी वृद्धि देखते हैं । रवांडा, बुरुन्डी, नाइजीरिया, कांगो, जॉर्जिया, अज़रबैजान, उक्रेन आदि देशों में जातीय संघर्षों और नरसंहार के दृश्य विचलित कर देने वाले हैं। इन साबके अतिरिक्त, हाल के वर्षों में आतंकवाद भी एक वैश्विक चुनौती के रूप में उभरा है।

चित्र-3

रवांडा नरसंहार के अवशेष

स्रोत: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nyamata_Memorial_Site_13.jpg accessed on 18 February 2015

समझ की परख

(रिक्त स्थानों की पूर्ति करें)

6 गुटनिरपेक्षता आन्दोलन----के दशक में हुआ।

7 नाटो की स्थापना----में हुई थी।

8 हाइपरपॉवर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग----ने किया।

9 दक्षिण सूडान----को अस्तित्व में आया।

10 शीत युधोत्तर युग में सैन्य गठबन्धनों के स्थान पर----की प्रक्रिया अधिक प्रचलन में आयी है।

1.3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम

शीत युद्ध के समापन के पश्चात से अब तक के लगभग ढाई दशकों का सफ़र अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है। सोवियत संघ के पतन के समय जब 'नवीन विश्व व्यवस्था' के निर्माण की चर्चा जोरों पर थी तभी इराक ने कुवैत पर कब्ज़ा जमा कर एक नए संकट को जन्म दिया जिसकी अंततः परिणति खाड़ी युद्ध के रूप में हुई। अफगानिस्तान में 1990 के दशक में तालिबान अपनी जड़ें जमाता रहा किन्तु विश्व समुदाय द्वारा उसकी उपेक्षा की जाती रही तथापि 11 सितम्बर 2001 को संयुक्त राज्य अमरीका में आतंकवादी हमले की घटना के पश्चात 'आतंकवाद के खिलाफ युद्ध' की मुहिम चल पड़ी। आर्थिक दृष्टि से वैश्वीकरण की बयार को 'विश्व व्यापार संगठन' की स्थापना से नया संबल मिला किन्तु 2008 की वैश्विक मंदी ने संसार को झकझोर कर रख दिया । इन सबके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पर्यावरणीय मुद्दे भी जोर शोर से उठे । इसके अतिरिक्त, शीत युधोत्तर युग में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और इसकी कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता भी गंभीर बहस के मुद्दे बने रहे।

1.3.1 खाड़ी युद्ध

शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही साथ दुनिया को जिस नवीन संकट का सामना करना पडा वह थी पश्चिम एशिया में इराक द्वारा कुवैत के अधिग्रहण की समस्या। इराक ने 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर सैन्य आक्रमण कर दिया और कुछ ही घंटो के अन्दर इस पर कब्जा कर लिया। शीघ्र ही इराक ने कुवैत को अपना उन्नीसवां प्रान्त भी घोषित कर दिया। संयुक्त राज्य अमरीका सहित विश्व के तमाम देशों ने इराक के इस कदम की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव संख्या 660 के तहत इराक की कुवैत से वापसी की अपील की गयी और 6 अगस्त 1990 को पारित प्रस्ताव संख्या 661 द्वारा इराक के खिलाफ तत्काल आर्थिक प्रतिबन्ध लागू किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस संकट का कूटनीतिक हल निकालने का प्रयास किया गया किन्तु इराक ने कुवैत से कब्ज़ा हटाने से इनकार कर दिया और तर्क दिया कि कुवैत प्रथम विश्व युद्ध तक उसका ही हिस्सा रहा था और इसके पश्चात अन्यायपूर्ण ढंग से अलग कर दिया गया था। इस प्रकार इराकी सरकार एक ऐतिहासिक त्रुटि को सुधारने का प्रयास कर रही थी। इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इस संकट को अरब-इजराइल संघर्ष से भी जोड़ने का प्रयास किया। कूटनीतिक प्रयासों के लम्बे दौर के बाद जब यह स्पष्ट हो गया कि इराक कुवैत से शांतिपूर्ण तरीकों से कब्जा नहीं हटाने वाला तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 29 नवम्बर 1990 को

प्रस्ताव संख्या 678 पारित किया जिसके तहत इराक को तक 1991 जनवरी 15कुवैत से निकासी का अंतिम समय दिया गया और इसका अनुपालन न होने की दशा में इराक के खिलाफ सैन्य कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान कर दी गयी।

चित्र-4

खाड़ी युद्ध के दृश्य

स्रोत: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gulf_War_Photobox.jpg accessed on 12 November 2014

इस बीच संयुक्त राज्य अमरीका ने इराक पर सैन्य हमले की तैयारी प्रारंभ कर दी और एक 'गठबंधन सेना' का निर्माण किया गया जिसमें लगभग 30 देशों ने भागीदारी करने को सहमति प्रदान की । वास्तविक तौर पर इस गठबंधन में छः देशों ने अपने सैन्य बल भेजे- संयुक्त राज्य अमरीका, सऊदी अरब, ब्रिटेन, फ्रांस, मिस्र और सीरिया । इनमे सबसे अहम् भागीदारी संयुक्त राज्य अमरीका के ही थी और युद्ध में भाग लेने वाले कुल 750,000 सैनिकों में से लगभग 540,000 अमरीकी ही थे । दूसरी ओर इराक को जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, यमन, ट्यूनिशिया और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन जैसे राष्ट्रों से नैतिक समर्थन प्राप्त था, यद्यपि किसी भी देश ने उसकी प्रत्यक्ष सैनिक मदद नहीं की । इस प्रकार यह युद्ध वस्तुतः अमरीका और इराक के मध्य हुआ। गठबंधन सेनाओं द्वारा 17 जनवरी 1991 को इराक पर हवाई हमलों की शुरूआत हुई और 28 फरवरी 1991 को कुवैत की मुक्ति के साथ ही समाप्त हुआ।

मानचित्र-4

ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म (फ़रवरी 1991): सैन्य गतिविधियां

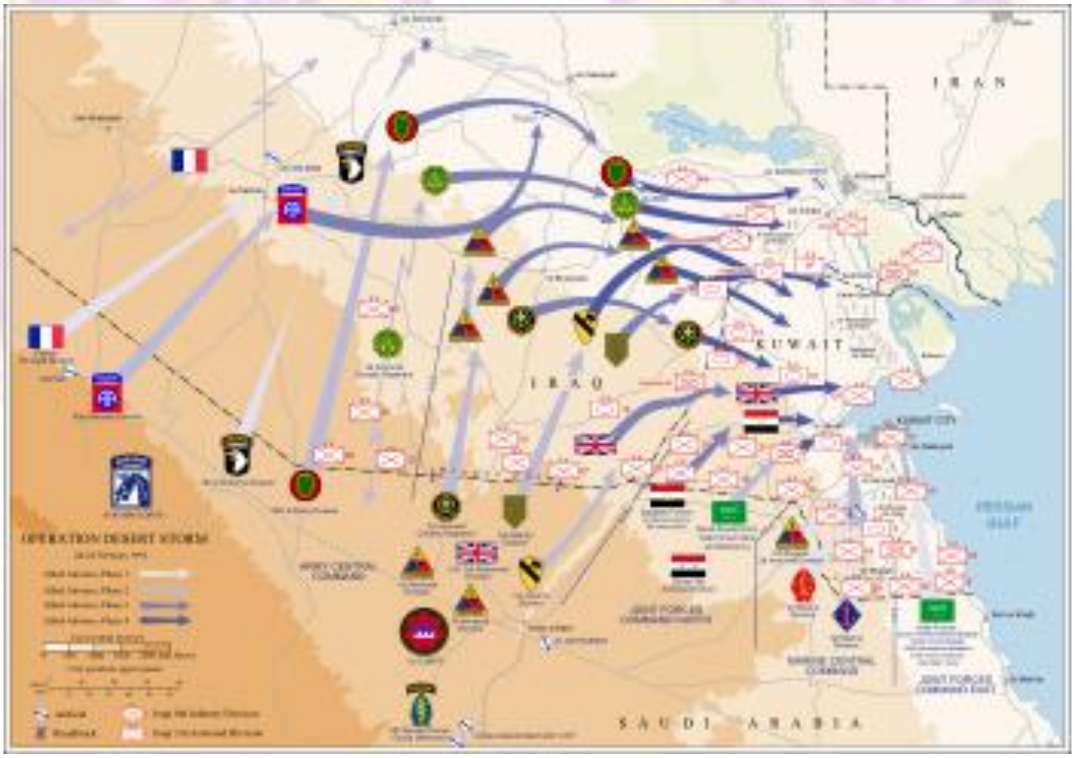

स्रोत : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DesertStormMap_v2.svg accessed on 3 November 2014

यद्यपि खाड़ी युद्ध फरवरी 1991 में ही समाप्त हो गया था किन्तु इराक पर आर्थिक प्रतिबन्ध दिसम्बर 2003 तक जारी रहे जब तक कि सद्दाम हुसैन को अमरीका द्वारा गिरफ्तार नहीं कर लिया गया । इस अवधि में इराक पर परमाणु हथियारों और अन्य विध्वंसक सामग्री छुपाने का आरोप लगाया गया और कई बार इस हेतु निरीक्षण का दबाव बनाया गया। वर्ष 2003 में संयुक्त राज्य अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लिये बिना ही इराक पर हमला कर दिया और सद्दाम हुसैन को अपदस्थ कर दिया । महीनों की मशक्कत के बाद अमरीका ने सद्दाम हुसैन को एक सैनिक बंकर से गिरफ्तार कर लिया और उन्हें दिसम्बर 2006 में फांसी पर लटका दिया गया।

चित्र-5

सद्दाम हुसैन: गिरफ्तारी के पश्चात

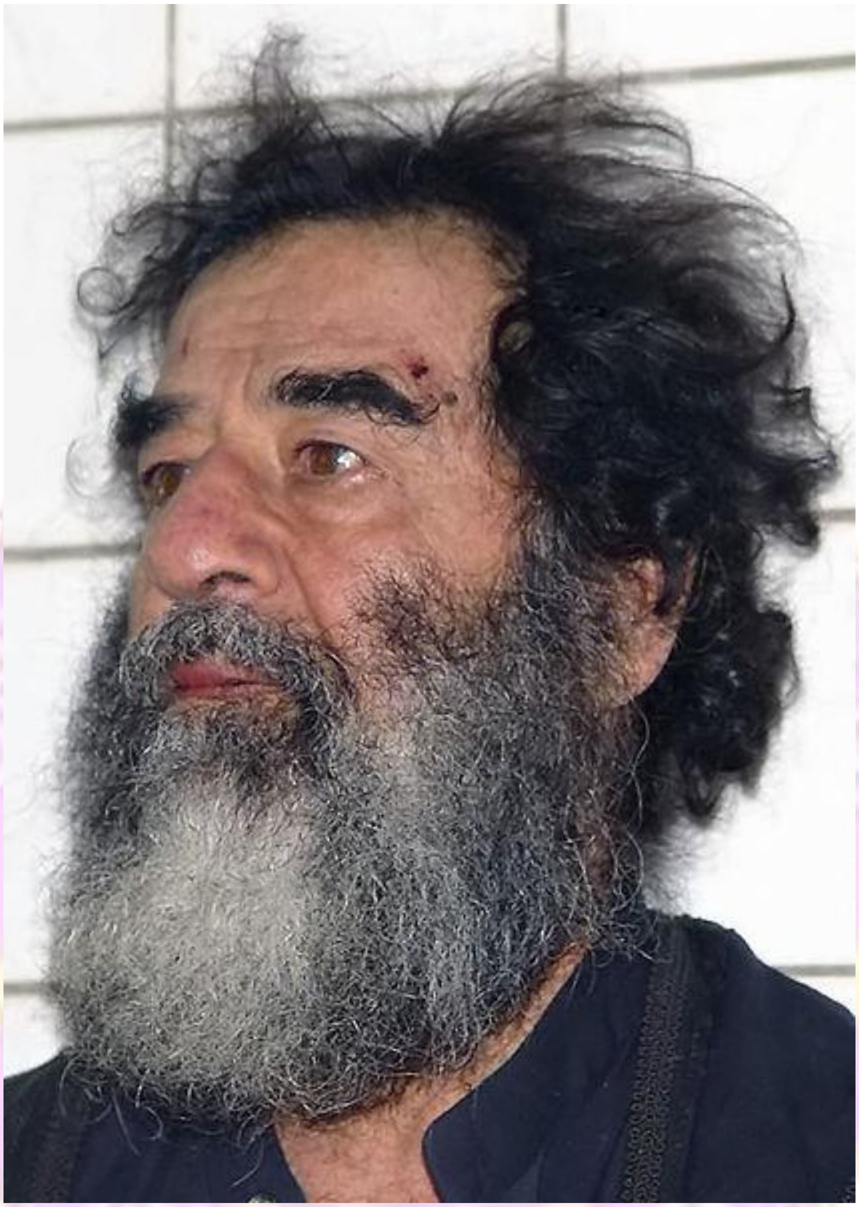

स्रोत : http://commons.wikimedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86#mediaviewer/File:Saddamcapture.jpg accessed on 13 January 2015

1.3.2 अफगानिस्तान में तालिबानी शासन

अफगानिस्तान में 1979 सोवियत संघ ने सैन्य हस्ताक्षेप किया तथा वहां 1989 तक सोवियत सेना तैनात रही। सोवियत सेनाओं की वापसी ने देश में शक्तिशून्यता को जन्म दिया और अफगानिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गये । वहां मौजूद कट्टरपंथी ताकतों ने इन परिस्थितियों का फायदा उठाया

और मूलतः दक्षिणी अफगानिस्तान में एक इस्लामी कट्टरपंथी राजनीतिक-धार्मिक आंदोलन -'तालिबान' की शुरूआत हुई। इसमें प्रमुख रूप से मदरसों में शिक्षित पश्चिम विरोधी पश्तून लोग शामिल थे जो कि देश में देवबंदी इस्लामी और पश्तून परम्पराओं की स्थापना करना चाहते थे। इन्हें पड़ोसी पाकिस्तान सुर कुछ हद तक सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के कट्टरपंथियों का समर्थन प्राप्त था । 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और 2000 तक आते आते अफगानिस्तान का लगभग 90 प्रतिशत भू-भाग में तालिबानी सरकार के नियंत्रण में आ गया । तालिबान सरकार न केवल पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध थी बल्कि देश की अन्य अल्पसंख्यक प्रजातियों के प्रति भी अत्यंत असहिष्णु थी। तालिबान लड़ाकों ने हजारा और उजबेक अल्पसंख्यकों का व्यापक कत्लेआम किया और बामयान घाटी में अवस्थित में हजारों वर्षों पुरानी बुद्ध की प्रतिमाओं का मार्च 2001 में विध्वंस कर दिया। बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के हनन, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों को प्रश्रय देने की बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान के इस घटनाक्रम की प्रायः उपेक्षा ही की । किन्तु संयुक्त राज्य अमरीका में आतंकवादी हमले के पश्चात दुनिया भर का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ और अंततः दिसम्बर 2001 में तालिबानी सरकार का पतन हो गया।

महत्वपूर्ण तथ्य-3

अफगानिस्तान की बामयान घाटी में बुद्ध की प्रतिमा

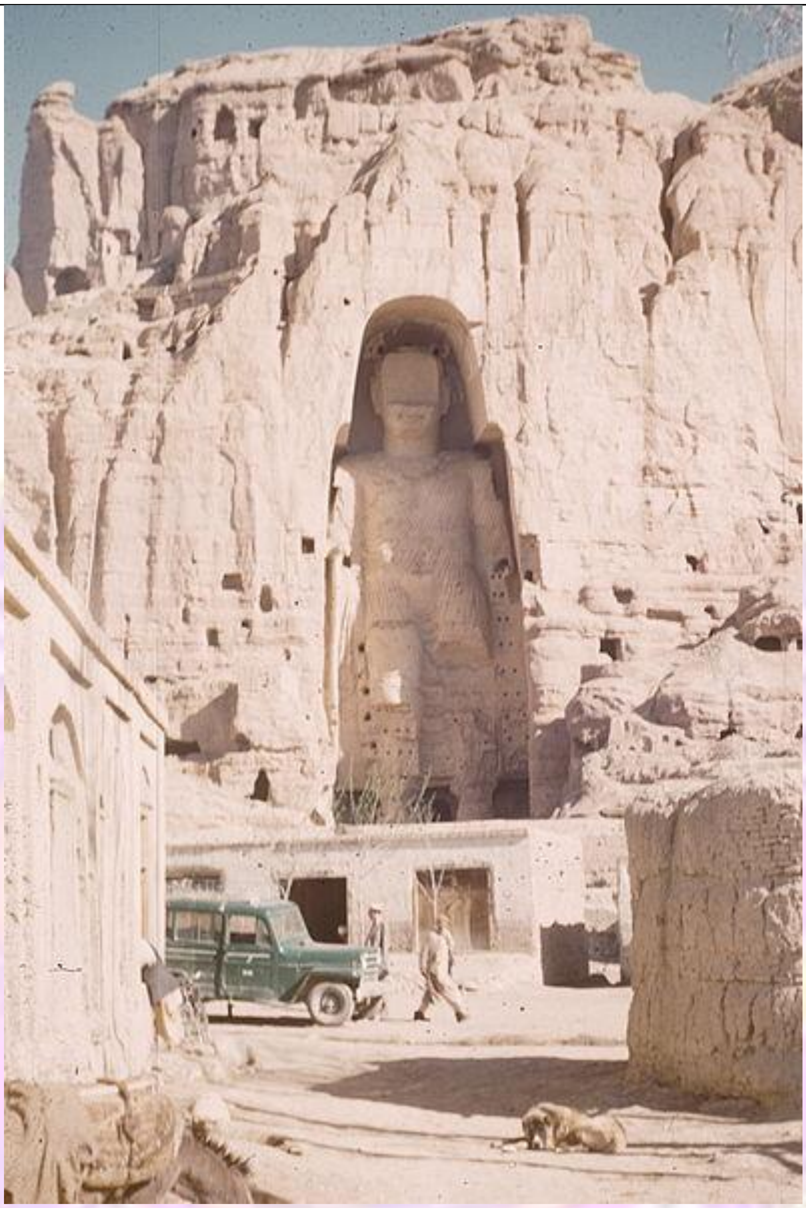

स्रोत: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buddhas_of_Bamiyan_D22.jpg accessed on 13 February 2015

बामयान घाटी अफगानिस्तान में हज़ाराजत क्षेत्र में अवस्थित है । यहां पर गुफा में उत्कीर्ण गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं थीं जिनका निर्माण संभवतः छठवी शताब्दी में हुआ था । मार्च 2001 में अफगानिस्तान की सरकार ने देश में मौजूद समस्त प्रतिमाओं को नष्ट करने का आदेश दिया जिसका अनुपालन करते हुए 21 मार्च 2001 को इन प्रतिमाओं को विध्वंस कर दिया गया।

1.3.3 अमेरिका में आतंकवादी हमला

इक्कीसवीं सदी की शुरूआत एक ऐसी घटना से हुई जिसने न केवल संयुक्त राज्य अमरीका जैसी महाशक्ति को हिला कर रख दिया बल्कि दुनिया भर में बेचैनी पैदा कर दी। यह घटना थी संयुक्त राज्य अमरीका में 11 सितम्बर 2001 को हुआ आतंकवादी हमला । यह हमला अलकायदा द्वारा रची गयी साजिश का परिणाम था जिसे 19 आत्मघातियों ने अंजाम दिया था । इन आत्मघातियों ने अमेरिका के चार वाणिज्यिक विमानों का अपहरण कर लिया और उनमें से दो को न्यूयॉर्क शहर की व्यावसायिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया, तीसरे विमान को वाशिंगटन डी॰सी॰ के पास स्थित पेंटागन में टकरा दिया जबकि चौथे विमान से वह अपने मंसूबे पूरे करने में नाकामयाब रहे और वह पेंसिल्वेनिया में एक खेत में जा गिरा। इन हमलों में आत्मघाती हमलावरों सहित लगभग 3000 लोग मारे गए।

चित्र-6

आतंकवादी हमलों के पश्चात वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का दृश्य

स्रोत:

http://hi.wikipedia.org/wiki/11_%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%B0_2001_%E0%A4%95%E0%A5%87_%E0%A4%B9%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%87#mediaviewer/File:September_11_2001_just_collapsed.jpg accessed on 13 February 2015

1.3.4 आतंकवाद के खिलाफ युद्ध

विश्व इतिहास में आतंकवादी संगठनों का अस्तित्व एवं उनके द्वारा की जाने वाली विध्वंसक कार्यवाहियां सदैव से ही राष्ट्र-राज्यों के लिये गंभीर चुनौती रही हैं । भारत, इजराइल समेत दुनिया के अनेक देश

दशकों से आतंकवाद के गंभीर शिकार रहे थे किन्तु संयुक्त राज्य अमरीका में आतंकवादी हमलों के पश्चात आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती के रूप में उभरा । अमेरिका में आतंकवादी हमले के चंद दिनों पश्चात 20 सितम्बर 2001 को राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अमेरिकी संसद के विशेष संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए 'आतंकवाद के खिलाफ युद्ध' की घोषणा की । संयुक्त राज्य अमरीका में हुए आतंकवादी हमलों के आलोक में 28 सितम्बर 2001 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने एकमत से प्रस्ताव संख्या 1373 पास किया जिसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की किसी भी घटना को वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिये चुनौती माना गया संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधीन राष्ट्रों को व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर इनसे निपटने के प्रयास करने की स्वतंत्रता दी गयी। इसके पश्चात प्रायः हर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्तालाप के मंचों पर आतंकवाद के निपटने सम्बन्ध में समझौते किये गये और विभिन्न देशों ने अनेक नवीन नियम कानूनों का निर्माण किया।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने नाटो सहयोगियों के साथ मिलकर 7 अक्टूबर 2001 को 'सतत स्वतंत्रता अभियान' (Operation Enduring Freedom) की शुरूआत की । चूंकि अमेरिकी हमलों का सूत्रधार 'अलकायदा' तालिबान शासित अफगानिस्तान की उपज था अतः इस अभियान के तहत पहला हमला वहां किया गया और दिसम्बर 2001 में तालिबान को विस्थापित कर अंतरिम सरकार की स्थापना की गयी । किन्तु अलकायदा पूर्वी अफगानिस्तान के सुदूरवर्ती स्थानों में सक्रिय रहा और इसके मुखिया ओसामा बिन लादेन को आखिरकार 2011 में पाकिस्तान में पकड़ा जा सका । इस बीच 29 जनवरी 2002 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अपने एक भाषण में 'पाप की धुरी वाले राज्य' (Axis of Evils States) की नवीन अवधारणा गढ़ी जिसके अंतर्गत इराक, ईरान और उत्तर कोरिया को अमेरिका का शत्रु माना गया तथा इनको आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के अगले चरण के रूप में चित्रित किया गया। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के क्रम में अमेरिका ने फ़िलीपीन्स, सोमालिया, ट्रांस-सहारा, इराक, लीबिया जैसे अनेक देशों में सैन्य कार्यवाहियां की।

किन्तु आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में प्रायः अमरीका द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा की गयी है, मानवाधिकारों का व्यापक दमन किया गया है । इसके साथ ही साथ अमेरिकी कार्यवाहियां प्रायः राष्ट्रीय हितों से प्रेरित रही हैं न कि आतंकवाद के समूल उन्मूलन की भावना के अनुरूप । इन सबने जाने अनजाने में दुनिया के अनेक हिस्सों में चरमपंथ के प्रसार और अनेक नवीन आतंकवादी संगठनों के प्रसार को बढ़ावा दिया है जिसका ज्वलंत उदाहरण है हाल में गंभीर चुनौती के रूप में उपजा आईएस आईएस।

चित्र-7

आतंकवाद के खिलाफ युद्ध

स्रोत: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:War_on_Terror_montage1.png accessed on 3 February 2015

महत्वपूर्ण तथ्य-4
आईएसआईएस के नियंत्रण वाले क्षेत्र

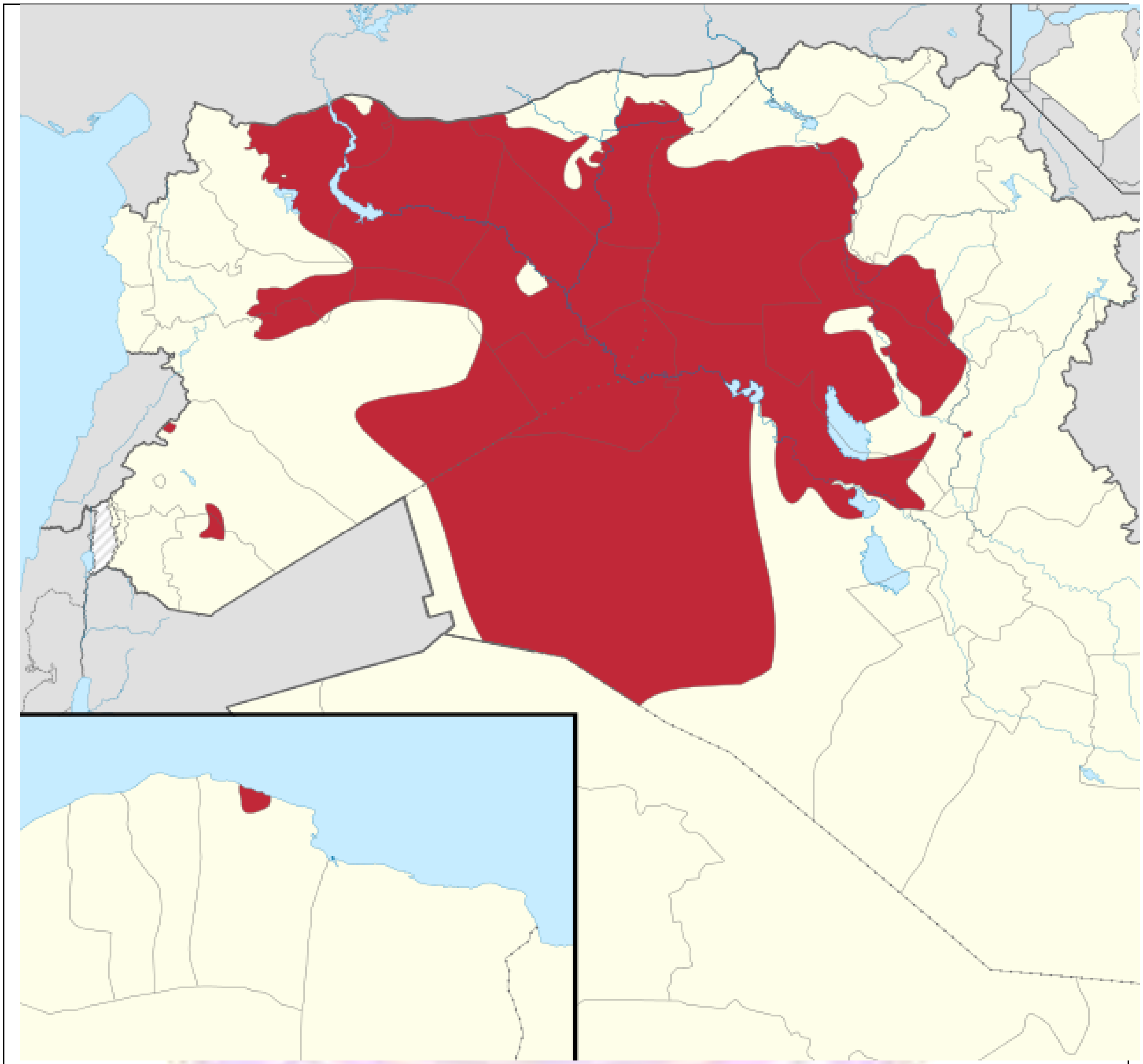

स्रोत: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Territorial_control_of_the_ISIS.svg accessed on 13 February 2015

'इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ' इराक एवं सीरिया में सक्रिय जिहादी सुन्नी सैन्य समूह है। अरबी भाषा में इस संगठन का नाम है 'अल दौलतुल इस्लामिया फिल इराक वल शाम'। इस संगठन का गठन अप्रैल 2013 में हुआ। इब्राहिम अव्वद अल-बद्री उर्फ अबु बक्र अल-बगदादी इसका मुखिया है। यह अल कायदा से भी अधिक मजबूत और क्रूर संगठन के तौर पर जाना जाता हैं। यह दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन है जिसका बजट 2 अरब डॉलर का है। इसने अपने मुखिया को विश्व के सभी मुसलमानों का खलीफा घोषित किया है। विश्व के अधिकांश मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों को सीधे अपने

राजनीतिक नियंत्रण में लेना इसका घोषित लक्ष्य है (स्रोत: http://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%8F%E0%A4%B8%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%8F%E0%A4%B8 accessed on 23 February 2015)।

1.3.5 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना

शीत युधोत्तर युग का एक महत्वपूर्ण विकास है- विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। यह संगठन 1 जनवरी 1995 को जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड (गैट) के स्थान पर अस्तित्व में आया। इस संगठन में 160 सदस्य हैं। यह एक व्यापक व्यापार समझौता है जिसके अंतर्गत पण्य वस्तुओं का व्यापार, सेवा व्यापार और बौद्धिक सम्पदा अधिकार जैसे अनेक विषय आते हैं। यह सदस्य देशों के मध्य बिना भेदभाव के सामानता पर आधारित मुक्त व्यापार की भावना पर आधारित है किन्तु इसके अंतर्गत अनेक मसलों पर विकसित और विकासशील देशों के मध्य हितों का टकराव दृष्टिगोचर होता है । विकासशील देशों में अक्सर इसे संशय की नजर से देखा जाता है और अनेक बार संगठन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं।

मानचित्र-5

विश्व व्यापार संगठन के सदस्य

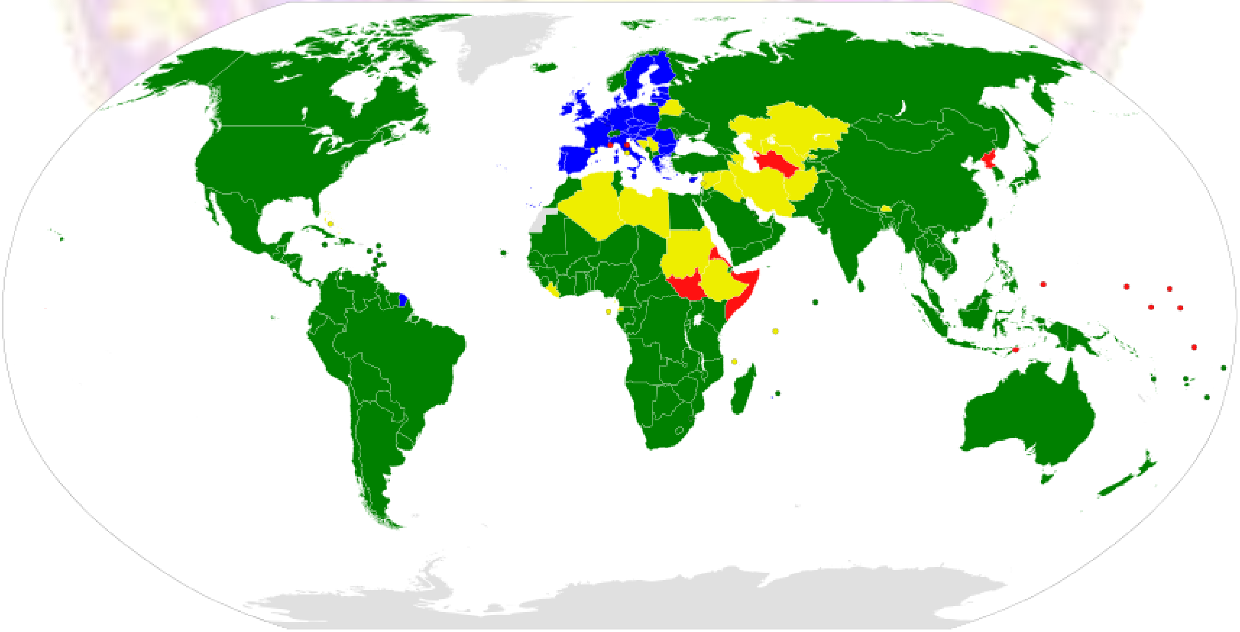

Members Members, dually represented by the European Union Observers Non-members

स्रोत:

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization#mediaviewer/File:WTO_members_and_observers.svg accessed on 12 November 2014।

1.3.6 पर्यावरणीय मुद्दे

चित्र-8

ग्लोबल वार्मिंग के खतरों को दर्शाता एक कार्टून

स्रोत: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Global_warming.jpg accessed on 22 December 2014।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पर्यावरणीय मुद्दे यूं तो सत्तर के दशक से ही विद्‌यमान रहे थे और इस सम्बन्ध में अनेक समझौतों का सूत्रपात शीत युद्ध के दिनों में ही हो चुका था । किन्तु शीत युधोत्तर विश्व में पर्यावरणीय समस्याएँ वैश्विक चुनौती के रूप में उभरीं और इनके निवारण हेतु दुनिया भर में वार्ताओं के सिलसिले में तेजी आई। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैव विविधता पर संकट, ओजोन पर्त

में छेंद जैसी समस्याओं की ओर दुनिया भर का ध्यान आकृष्ट हुआ। इस सन्दर्भ में शीत युद्ध के अंत के उपरान्त पहला महत्वपूर्ण प्रयास जून 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डि जेनीरो में आयोजित 'पृथ्वी सम्मेलन' के रूप में सामने आया जिसमें 182 देशों के 20,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रियो घोषणापत्र में इस बात पर बल दिया गया कि दीर्घकालीन आर्थिक विकास तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब इसे पर्यावरण की सुरक्षा से जोडा जाए तथा इसे प्राप्त करने हेतु सभी राष्ट्रों को एक नई वैश्विक साझेदारी कायम करने की जरूरत है जिसमें सरकार के साथ-साथ वहाँ के लोगों तथा नागरिक समाज का भी शामिल होना जरूरी है। रियो सम्मेलन में-जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा संबंधी अनुबंध, जैव विविधता पर अनुबंध और कार्यसूची-21 पर सहमति बनी। वैश्विक तापमान में बढोतरी की चुनौती से निपटने के लिए 'जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा संबंधी अनुबंध' को कार्यरूप देने के लिये 11 दिसंबर 1997 को 'क्योटो प्रोटोकॉल' स्वीकार किया गया जिस पर 55 देशों ने हस्ताक्षर किए। रियों शिखर सम्मेलन के दस वर्ष बाद सतत विकास का आकलन करने के लिए 2002 में जोहान्सबर्ग 'विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन' का आयोजन किया। इसी क्रम में 20-22 जून 2012 को रियो डि जेनीरो में पुनः 'पृथ्वी सम्मेलन' आयोजित किया गया जिसमें 172 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। किन्तु इन वैश्विक प्रयासों में घोषणाओं और वास्तव में की गयी कार्यवाहियों में जमीन आसमान का अंतर दिखता है और प्रायः हर प्रयास यथार्थ में परिणित होता नहीं दिखता।

1.3.7 संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका

चित्र-9

न्यूयार्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय

स्रोत:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:United_Nations_Headquarters_in_New_York_City,_view_from_Roosevelt_Island.jpg accessed on 15 December 2014।

शीत युधोत्तर युग में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में भी व्यापक बदलाव दिखा है । जहाँ एक ओर, इसमें संयुक्त राज्य अमरीका का प्रभाव बढ़ा है और कई आलोचक तो संयुक्त राष्ट्र संघ को संयुक्त राज्य अमरीका का विस्तार मात्र मानते हैं जिसका कार्य अमरीकी नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति दिलवाना है। वहीं दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में 'वीटो' के प्रयोग में कमी, संयुक्त राष्ट्र की शांति रक्षण गतिविधियों का प्रसार और विविध सामाजिक क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के बढ़ते दायरे को सकारात्मक पहलू के रूप में स्वीकार किया जाता है जिनमें से सबसे उल्लेखनीय है संयुक्त राष्ट्र के महत्वाकांक्षी 'सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य'। इन सबके बीच बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में सुधार की मांग भी जोर पकडती जा रही है।

महत्वपूर्ण तथ्य-5

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी)

सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों का निर्धारण संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया है।

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी)- आठ अंतरराष्ट्रीय विकास लक्ष्य हैं:

- चरम गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन
- सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा पाना
- लिंग समानता को बढ़ावा देना और महिला सशक्तीकरण
- बाल मृत्यु दर में कमी
- मातृ स्वास्थ्य में सुधार
- एचआईवी / एड्स, मलेरिया, और अन्य रोगों से मुक्ति
- पर्यावरण की सततता सुनिश्चित करना
- विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी विकसित करना

इन्हें वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दि शिखर सम्मेलन में 'संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि घोषणा' के अंतर्गत अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के सभी 189 सदस्य राज्यों और कम से कम 23 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने वर्ष 2015 तक सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।

2015 के बाद का एजेंडा

सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के 2015 के अंत में समापन के साथ, दुनिया के नेताओं ने लोगों के जीवन में सुधार लाने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पृथ्वी की रक्षा करने के लिए एक महत्वाकांक्षी , दीर्घकालिक रणनीति का आह्वान किया है। इस 2015 के बाद के विकास एजेंडा में गरीबी और भुखमरी के समापन, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार , शहरों को अधिक टिकाऊ बनाने , जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने , और महासागरों और जंगलों की रक्षा सहित कई मुद्दों के शामिल होने की उम्मीद है।

इस दिशा में सरकारें बातचीत की प्रक्रिया में हैं और नागरिक समाज, युवा लोग, कारोबारी और अन्य सम्बद्ध पक्ष इस वैश्विक वार्तालाप में सहभागी हैं। सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में आयोजित हो रहे एक शिखर सम्मेलन में इस एजेंडा को विश्व नेताओं द्वारा अपनाने की उम्मीद की जा रही है।

समझ की परख

(बहुविकल्पीय प्रश्न)

11 संयुक्त राज्य अमरीका में आतंकवादी हमला कब हुआ?

(क) 11 सितम्बर 2011 (ख) 13 दिसम्बर 2001 (ग) 11 सितम्बर 2001 (घ) 26 नवम्बर 2008

12. सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को---- तक प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी थी।

(क) सन् 2015 ई. (ख) सन् 2005 ई. (ग) सन् 2010 ई. (घ) सन् 2020 ई.

13 विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया?

(क) 1 जनवरी 1947 (ख) 1 दिसम्बर 2001 (ग) 13 दिसम्बर 1991 (घ) 1 जनवरी 1995

14 तालिबानी शासन किस देश में था?

(क) पकिस्तान (ख) अफगानिस्तान (ग) लीबिया (घ) अल्जीरिया

15 इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य नहीं है?

(क) जापान (ख) चीन (ग) ब्रिटेन (घ) फ्रांस

सारांश

- सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध के अंत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्रांतिकारी बदलाव लाये। जहाँ एक ओर सैद्धांतिक दृष्टि से विद्वानों ने 'नवीन विश्व व्यवस्था' के उदय की व्याख्याएँ दीं तो वहीं व्यवहारिक तौर पर इस युग में अनेक नवीन संभावनाओं और चुनौतियों ने दस्तक दी।
- शीत युधोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या फ्रांसिस फुकुयामा ने 'इतिहास के अंत' की अवधारणा के रूप में की जबकि हटिंगटन के अनुसार शीत युधोत्तर युग में संघर्ष अपने नवीन स्वरुप में अभिव्यक्त होगा जिसे उन्होंने 'सभ्यताओं के संघर्ष' के रूप में चित्रित किया।
- चोम्स्की के अनुसार , मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अमेरिकी प्रभुत्व की संरचना करती है और निश्चित रूप से सौहार्दपूर्ण नहीं है।

- शीत युधोत्तर युग में अनेक प्रतिद्वंदी रूझान दृष्टिगोचर होते हैं -वैश्वीकरण और विखंडन ; एकधुव्रीयता और बहुधुव्रीयता ; आर्थिक एकीकरण और सैन्य गठबंधन ; अमेरिकी वर्चस्व और तृतीय विश्व; ग्लोबल कॉमन्स, अंतर-राज्यीय प्रतिद्वंद्विता और वैश्विक खतरे।
- शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही साथ दुनिया को जिस नवीन संकट का सामना करना पडा वह थी पश्चिम एशिया में इराक द्वारा कुवैत के अधिग्रहण की समस्या । यह घटना खाड़ी युद्ध का जनक बनी।
- हालाँकि 28 फरवरी 1991 को कुवैत को मुक्त करा लिया गया किन्तु इराक पर आर्थिक प्रतिबन्ध दिसम्बर 2003 तक जारी रहे जब तक कि सद्दाम हुसैन को अमरीका द्वारा गिरफ्तार नहीं कर लिया गया।
- अफगानिस्तान में तालिबानी शासन की शुरूआत 1996 में हुई तथा 2000 तक आते आते अफगानिस्तान का लगभग 90 प्रतिशत भू-भाग में तालिबानी सरकार के नियंत्रण में आ गया।
- संयुक्त राज्य अमरीका में 11 सितम्बर 2001 को हुआ आतंकवादी हमला, अलकायदा द्वारा रची गयी साजिश का परिणाम था।
- अमेरिका में आतंकवादी हमले के चंद दिनों पश्चात 20 सितम्बर 2001 को राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अमेरिकी संसद के विशेष संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए 'आतंकवाद के खिलाफ युद्ध' की घोषणा की।
- आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में प्रायः अमरीका द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा की गयी है, मानवाधिकारों का व्यापक दमन किया गया है । इसके साथ ही साथ अमेरिकी कार्यवाहियां प्रायः राष्ट्रीय हितों से प्रेरित रही हैं न कि आतंकवाद के समूल उन्मूलन की भावना के अनुरूप।
- विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को अस्तितत्व में आया। इस संगठन में 160 सदस्य हैं।
- शीत युधोत्तर विश्व में पर्यावरणीय समस्याएँ वैश्विक चुनौती के रूप में उभरीं और इनके निवारण हेतु दुनिया भर में वार्ताओं के सिलसिले में तेजी आई।
- शीत युधोत्तर युग में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में व्यापक बदलाव दिखा है।
- बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में सुधार की मांग भी जोर पकडती जा रही है।

अभ्यास के लिये प्रश्न

1) शीत युधोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरुप पर विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोणों की चर्चा करें।
2) शीत युधोत्तर युग में व्याप्त प्रतिद्वंद्वी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें।
3) खाड़ी युद्ध पर निबंध लिखें।

4) आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का आलोचनात्मक विवेचन करें।

5) संक्षिप्त टिप्पणी करें:

क) सभ्यताओं का संघर्ष

ख) विश्व व्यापार संगठन

ग) ग्लोबल कॉमन्स

घ) पर्यावर्णीय मुद्दे

पारिभाषिक शब्द

- **सभ्यताओं का संघर्ष :** राजनीति-विज्ञानी सैमुएल पी. हंटिंगटन द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धान्त जिसके अनुसार शीत-युद्धोत्तर संसार में लोगों की सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान ही संघर्षों का मुख्य कारण होगी।
- **कल्याणकारी राज्य:** कल्याणकारी राज्य में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को इस प्रकार नियमित किया जाता है जिससे समाज के वंचित तबकों तक युक्तिसंगत सहायता पहुंचाई जा सके और सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि से राज्य के अन्दर कुछ अनिवार्य सेवाओं - स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के साधन, मनोरजंन के साधन , बीमारी एवम् वृद्धावस्था में सहायता इत्यादि का जाल बिछाकर जनसाधरण के लिये सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- **प्रजाति:**यह एक प्रकार की सामाजिक पहचान है जो कि एक विशेष नस्लीय,जातीय , राष्ट्रीय या सांस्कृतिक समूह और उस समूह से सम्बद्ध परम्पराओं , विश्वासों और भाषा आदि के आधार पर निर्धारित होती है।
- **नरसंहार:** नरसंहार का तात्पर्य बहुत सारे व्यक्तियों की सामूहिक हत्याओं से है। यह हत्याएँ अकारण, निजी स्वार्थ हेतु अथवा अपराध या युद्धजनित हो सकती हैं।
- **ऑपरेशन डेज़र्ट स्टोर्म:** गठबंधन सेनाओं द्वारा जनवरी 1991 में इराक पर हमले के लिये प्रयुक्त कोडवर्ड।

समझ की परख: उत्तर

उत्तर 1: गलत

उत्तर 2: सही .

उत्तर 3: गलत

उत्तर 4: सही

उत्तर 5: सही

उत्तर 6: साठ

उत्तर 7: 1949

उत्तर 8: पेरेग्रिन वोर्स्थोरने

उत्तर 9: 9 जुलाई 2011

उत्तर 10: आर्थिक एकीकरण

उत्तर 11: (ग) 11 सितम्बर 2001

उत्तर 12: (क) सन् 2015 ई.

उत्तर 13: (घ) 1 जनवरी 1995

उत्तर 14: (ख) अफगानिस्तान

उत्तर 15: (क) जापान

सन्दर्भ

1. स्रोत

गिल एस., 'कॉन्टराड़िकशन्स ऑफ़ यूएस सुपरमेसी' *सोशलिस्ट रजिस्टर 2005: द एम्पायर रीलोडेड* वॉल्यूम 41 पृ. 23-45।

कॉक्स एम., 'फ़्रॉम द कोल्ड वॉर टू द वॉर ऑन टेरर'; बेयलिस जे. और स्मिथ एस., *द ग्लोबलाइजेशन ऑफ़ वर्ल्ड पॉलिटिक्स*(नई दिल्ली: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2005) पृ. 131-157।

ब्रेज़ेज्न्सकी जेड., *ग्लोबल डोमिनेंस ओर ग्लोबल लीडरशिप* (न्यूयॉर्क: बेसिक बुक्स, 2005) पृ. 85-127।

थरबोर्न जी., 'पोल्स एंड टाईएन्गल्स ऑफ़ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप'; हादिज़ वी. आर. (संपा.) *एम्पायर एंड निएओ लिबेरलिस्म इन एशिया* (लन्दन: रूट्लेज, 2006) पृ. 23-37।

चोमस्की एन., इम्पीरियल एम्बिशंस: कन्वरसेशंस ऑन द पोस्ट 9/11 वर्ल्ड (न्यूयॉर्क, मेट्रोपोलिटन बुक्स, 2005)।

2. पठनीय सामग्री

किरास जे. दी., 'टेररिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन'; बेयलिस जे. और स्मिथ एस., *द ग्लोबलाइजेशन ऑफ़ वर्ल्ड पॉलिटिक्स*(नई दिल्ली: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2005) पृ. 131-157।

शर्मा एस. और गुप्ता आर. के., *भारत और दक्षिण एशियाई क्षेत्रवाद* (नई दिल्ली: बुक ऐज पब्लिशर्स, 2014)।

पन्त पी., *21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध* (नई दिल्ली: टीएमएच, 2012) पृ. 369-400।

3. वेबसाइट

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Malta_Summit#mediaviewer/File:Bush_and_Gorbachev_at_the_Malta_summit_in_1989.gif
2. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francis_Fukuyama_2005.jpg
3. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clash_of_Civilizations_map.png
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky#mediaviewer/File:Chomsky.jpg
5. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SocialistYugoslavia_en.svg
6. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SouthSudanStateshi.svg
7. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:History_of_NATO_enlargement.svg
8. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emperor_Obama,_by_Ranan_Lurie.png
9. http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming#mediaviewer/File:GISS_temperature_2000-09_lrg.png
10. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nyamata_Memorial_Site_13.jpg
11. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gulf_War_Photobox.jpg
12. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DesertStormMap_v2.svg
13. http://commons.wikimedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86#mediaviewer/File:Saddamcapture.jpg
14. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buddhas_of_Bamiyan_D22.jpg
15. http://hi.wikipedia.org/wiki/11_%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%B0_2001_%E0%A4%95%E0%A5%87_%E0%A4%B9%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%87#mediaviewer/File:September_11_2001_just_collapsed.jpg
16. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:War_on_Terror_montage1.png

17. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Territorial_control_of_the_ISIS.svg
18. http://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%8F%E0%A4%B8%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%8F%E0%A4%B8
19. **http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization#mediaviewer/File:WTO_members_and_observers.svg**
20. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Global_warming.jpg
21. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:United_Nations_Headquarters_in_New_York_City,_view_from_Roosevelt_Island.jpg